

# असाधारण EXTRAORDINARY)

भाग II—सण्ड 3—एप-सण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 251]

नई बिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 1985/एयेष्ठ 3, 1907

No. 251]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 1985/JYAISTHA 3, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रक्षा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## गृह मंद्रालय

नई दिल्ली, 21 मई, 1985

#### अधिसूचना

का. आ. 411 (अ):— केन्द्रीय गरकार ने, आंतकवादी केन्न (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 (1984 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करने हुए, भारत सरकार के गृह मंद्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 804(अ) तारीख़ 4 विसम्बर, 1984 के अधीन चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के चंडीगढ़ त्यायिक जोन की बाबत राजस्थान राज्य में अजमेर में एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय की स्थापना की है।

और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूचित अपराधों से संबंधित 6 मामले उत्पन्न हो चुके हैं; जो चंडीगट न्यायिक जोन में चटित हुए थे।

और चंडीगृह संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने केन्द्रोय सरकार की एक लिखित रिपोर्ट मेजी है, जिसमें इससे उपायद्ध अनुसूची में वितिद्धिष्ट अपराधों की बाबन उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन बोषणा करने के लिये अनुरोध किया गया है।

और केन्द्रीय सरकार की, चंडीगड़ संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को चक्त रिपोर्ट की, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों को उक्त मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को तथा अन्य सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि यह समीचीन है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थापित अक्तिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार. उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती है कि उक्त अपराक्षों का यिचारण राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थापित अतिन्क्ति विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

 $[ \dot{H} : 5/10/85-$ विश्विक सैल] एत. पी. नवानी, संयुक्त सचिव

		अनुमूची ————		
क, सं.	मामलों के विवरण	अपराध · .	न्यायिक जोन जिसमें अपराध किए गए	
1	2	3	. 4	
तारीव	ता एफआईआर सं . 293 1 3 . 10 . 1984 स्टेशन, बैस्ट, चंडीगक	भारतीय दंड सहिता की धारा 124-ए/153-वी	चंडीगढ़	

1	2	3	4
2.	मामला एकआईआर सं. 703 तारीख 5. 10. 1984 पुलिस स्टेशन, सैन्ट्रल, चंडीगढ़	भारतीय दंड संहिता की धारा 124/ए/153-ए	<b>चंडीगढ़</b>
3.	मामला एफआईआर सं, 222 तारीख 20.7,1984 पुलिस स्टेशन,धैस्ट, चंडीगढ़	भारतीय दंड संहिता की धारा 436	चंडीगढ
4.	मामला एफआईआरसं. 323 तारीख 19.4.1984 पुलिस स्टेशन, सैन्ट्रल, धंडीगढ़	भारतीय दंड संहिता की घारा 302	चंडीगढ
5.	मामला एफआईआर सं. 175 तारीख 19.4.1984 पुलिस स्टेशन, साउप, चंडीगढ़	भारतीय दंड संहिता की घारा 307	चंडीगढ़ं
6.	मामला एकबाईआर सं 378 तारीच 30.7.1984 पुलिस स्टेशन,ईस्ट, बंडीगढ़	मारतीय वंड संहिता की धारा 395	चंडीगढ़

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 24th May, 1985

### NOTIFICATION

S.O. 411 (E): Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984), has established an Additional Special Court at Ajmer in the State of Rajasthan in relation to the judicial zone of Chandigarh in the Union Territory of Chandigarh under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. GSR 804 (E) dated the 4th December, 1984;

And whereas six cases have arisen involving scheduled offences, specified in the Schedule annexed hereto, committed in the judicial zone of Chandigarh in the Union Territory of Chandigarh;

And whereas the Administration of the Union Territory of Chandigarh has forwarded to the Central Government a report in writing containing a request for making a declaration under sub-section(2) of section 7 of the said Act in respect of the offences specified in the Schedule annexed hereto;

And whereas the Central Government, having regard to the said report of the Administration of the Union Territory of Chandigarh, the provisions of sub-section (2) of section 4 of the said Act, the facts and circumstances of the said cases and all other relevant factors, is of the opinion that it is expedient that the said offences should be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of Rajasthan.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby declare that the said offences shall be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of Rajasthan.

[No. 5/10/85-Legal Cell] N. P. NAWANI, Jt. Secy.

#### THE SCHEDULE

S. No	Particulars of the cases	Offences	Judicial Zone in which the offences were committed
	Case FIR No. 293 dated 3-10-1984 PS West, Chandigarh.	Section 124-A/153-B of the IPC	Chandigarh
2.	Case FIR No. 703 dated 5-10-1984 PS Central, Chandigarh.	Section 124-A/153-A IPC	Chandigar <b>h</b>
3.	Case FIR No. 222 dated 20-7-1984 PS West, Chandigarh.	Section 436 IPC	Chandigar <b>h</b>
4.	Case FIR No. 323 dated 19-4-1984 PS Central, Chandigarh,	Section 302 IPC	Chandigar <u>h</u>
5.	Case FIR No. 175 dated 19-4-1984 PS South, Chandigarh.	Section 307 IPC	Chandigarh
6.	Case FIR No. 378 dated 30-7-1984 PS East, Chandigarh.	Section 395 IPC	Chandigurh